**विदेशी धनराशियों का उपयोग न किया जाना**

895. **श्री राम जेठमलानी:**
**श्री ईश दत्त यादव:**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1993 तक वित्तीय संस्थाओं से ऋण और अनुदान के रूप में प्राप्त अधिकांश धनराशि अप्रयुक्त पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो किस-किस विदेशी वित्तीय संस्था से प्राप्त की गई कितनी-कितनी धनराशि अप्रयुक्त पड़ी है;

(ग) सरकार को इस राशि पर कितना-कितना वचनबद्धता प्रभार अदा करना होगा;

(घ) क्या यह भी सच है कि इस राशि को विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा निर्माणाधीन परियोजनाओं पर खर्च किया जाना था; और

(ङ) यदि हां, तो दिसम्बर, 1993 के अंत तक किस-किस मंत्रालय या विभाग द्वारा विदेशों से प्राप्त ऋण में से कितनी-कितनी धनराशि का उपयोग किया गया और कितनी राशि अप्रयुक्त रह गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० अबरार अहमद): (क) और (ख) दिसम्बर, 1993 तक विदेशी वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण उपयोग में लाई गई और न लाई गई राशियों, के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं (नीचे देखिये)।

(ग) अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक तथा एशियाई विकास बैंक के मामले में 1993-94 में न निकाली गई शेष राशियों पर उपगत होने वाले प्रत्याशित वचनबद्धता प्रभार क्रमशः 34.05 करोड़ रुपए और 23.87 करोड़ रुपए के थे। आई०डी०ए०, आई एफ ए डी और ओ पी ई सी के मामले में किसी प्रकार के वचनबद्धता प्रभारों का भुगतान नहीं किया जाता।

(घ) और (ङ) प्रत्येक परियोजना के मामले में ऋणों में मंत्रालयों/विभागों द्वारा उपयोग में लाई गई राशि के ब्यौरे और न निकाली गई शेष राशियों के ब्यौरे अनुपत्र में दिये गए हैं। (देखिये परिशिष्ट 170, अनुपत्र सं० 20)

## विवरण

**विदेशी वित्तीय संस्थाओं से ऋणों के उपयोग के ब्यौरे (31.12.93 के अनुसार)**

(मिलियन अमरीकी डालरों में)

| संस्था का नाम | ऋण की राशि | उपयोग | न निकाली गई शेष राशि |
|---|---|---|---|
| ए डी बी | 3394.66 | 884.93 | 2509.736 |
| | 10693.923 | 6011.656 | 4682.267 |
| आई बी आर डी | 10693.923 | 6011.650 | 4682.267 |
| आई डी ए | 9361.241 | 4971.36 | 4389.485 |
| आई एफ ए डी | 139.850 | 109.309 | 30.541 |
| ओपेक | 61.500 | 43.228 | 18.272 |

**Excise Duty Paid by Parle**

896. SHRI V. GOPALSAMY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) how much central excise did Parle pay-during the last three years, year-wise;

(b) whether it is a fact that the Directorate of Central excise searched parle factories and offices; and

(c) if so, what has been the outcome thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

**Reduction in Staff by Public Sector Banks**

897. SHRI GURUDAS DAS GUPTA:
SHRI CHATURANAN MISHRA:

Will be Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the public sector banks have been asked to Trim their workforce; and

(b) if so, what is the estimated number of surplus staff and how their are going to be reduced;